C M Y K

www.vidarbhakibaat.in

Post Reg. No. RNP/NPCITY /169 /2015-2017

प्रखर... मुखर... स्वर

विदर्भ की बात

● वर्ष 17 ● अंक 245 नागपुर, मंगलवार, 1 अगस्त 2017 ● पृष्ठ 8 ● मूल्य ₹ 2

सुप्रभात

अब हर महीने 4 रुपए बढ़ेंगे घरेलू गैस सिलेंडर के दाम, सब्सिडी खत्म करेगी सरकार

नई दिल्ली

सरकार ने तेल कंपनियों को हर महीने सब्सिडी युक्त एलपीजी की कीमत चार रुपए बढ़ाने के लिए कहा है। सरकार अगले वर्ष मार्च तक एलपीजी पर पूरी सब्सिडी खत्म करना चाहती है। तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को यह बात कही।

इसके पहले सरकार ने इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम से प्रत्येक महीने सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) के दाम 2 रुपए बढ़ाने के लिए कहा था। धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा को दिए गए एक लिखित जवाब में बताया कि अब कीमत बढ़ोतरी को दोगुना कर दिया गया है, जिससे सब्सिडी को खत्म किया जा सके। हर घर को एक साल में सब्सिडाइज्ड रेट्स पर 12 सिलेंडर मिलते हैं। इसके बाद लिए जाने वाले सिलेंडर बाजार की दर पर मिलते हैं।

दिल्ली में अभी 14.2 किलोग्राम वाला सब्सिडाइज्ड एलपीजी 477.46 रुपये पर मिलता है। जबकि पिछले साल जून में यह 419.18 रुपये पर था, वहीं मार्केट रेट पर मिलने वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम अभी 564 रुपये है। प्रधान ने बताया कि जुलाई में एलपीजी पर सब्सिडी प्रति सिलेंडर 86.54 रुपये थी। देश में सब्सिडाइज्ड एलपीजी के 18.11 करोड़ कस्टमर्स हैं। इनमें 2.5 करोड़ गरीब महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें पिछले एक साल के दौरान प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत फ्री कनेक्शंस दिए गए थे। नॉन-सब्सिडाइज्ड कुकिंग गैस के यूजर की संख्या अभी 2.66 करोड़ है।

कीमत बढ़ाने के फैसले की ममता ने की आलोचना

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सब्सिडी वाली रसोईं गैस की कीमत में बढ़ोतरी के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले की आलोचना की और कहा कि भाजपा को सिर्फ धन की परवाह है।

तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा जनता से किए अपने वादों से पलट रही है और उसे लोगों की कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया, भाजपा जनता से वादा करती है और फिर इनसे पलट जाती है।

उन्हें सिर्फ धन की परवाह है। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे आम लोगों की चिंता है। पहले भी एलपीजी पर सब्सिडी वापस ली गई और फिर ऐसा किया गया। भाजपा को जनता की कोई फिक्र नहीं है।

जीएम फसलों पर सितंबर में आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली

जेनिटिकली मॉडिफाइड (जीएम) सरसों के उत्पादन मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से आगामी सितंबर माह में फैसला आ सकता है। केंद्र सरकार की ओर से मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा गया कि उसकी ओर से जीएम फसलों के उत्पादन पर सितंबर माह में निर्णय ले लिया जाएगा। मामले में मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की पीठ के समक्ष अतिरिक्त सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार जीएम फसलों के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है और जीएम फसलों के व्यवसायिक प्रयोग पर सुझाव मांगे हैं। इससे पहले 17 जुलाई की सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कहा था कि जीएम फसलों के व्यवसायिक इस्तेमाल पर सरकार की ओर से किसी तरह का अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। गौरतलब है कि जीएम फसलों के इस्तेमाल से कैंसर समेत कई तरह की बीमारियों के खतरे की आशंका जतायी गयी थी। इस आशंका के चलते कोर्ट की ओर से पिछले वर्ष 17 अक्टूबर को जीएम फसलों के व्यवसायिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी गयी थी।

गुजरात में बाढ़ से भारी तबाही, 213 लोगों की मौत

5 दिन बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में रहेंगे सीएम

पालनपुर

गुजरात में बाढ़ के कारण कई इलाके जलमग्न हैं। बाढ़ से भारी तबाही हो रही है। राज्य बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 213 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तरी गुजरात के बनासकांठा पाटन में हर ओर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। अकेले बनासकांठा में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, वहीं बाढ़ में 4225 मवेशियों की भी मौत हो गई है। ऐसे में हालात का जायजा लेने मुख्यमंत्री विजय रुपानी खुद बनासकांठा पहुंचे हैं और वह पांच दिनों तक यहीं रहेंगे।

बनासकांठा जिले में सबसे ज्यादा मौत बीती 21 जुलाई को हुई। यहां लगातार भारी बारिश के कारण तालाब ऊपर तक भर गए हैं। जब स्थानीय बांध में पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया, तो काफी पानी छोड़ दिया गया। इसकी वजह से आसपास के इलाकों में भारी तबाही हुई। कंट्रोल रूम के सूत्रों ने बताया कि 21 जुलाई को 61 लोगों की मौत हुई। इनमें से ज्यादातर लोग पानी में डूबने के कारण मारे गए।

मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने घोषणा की है कि वह राहत और पुनर्वास कार्य की देखरेख के लिए अगले पांच दिनों तक जिले में डेरा डालेंगे। रविवार को रुपानी ने 17 लोगों के रिश्तेदारों से मुलाकात की जो कंचरेज तालुक के खरिया गांव में मारे गए थे। खरिया और आसपास के गांवों में बनस नदी से कम से कम 28 शव बरामद किए गए हैं। उन्होंने पीड़ितों के परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत की और मुआवजा की राशि का भी वितरण किया।

सीएम विजय रुपानी का कहना है कि बनासकांठा के इतिहास में यह सदी की सबसे भयंकर बाढ़ है। वह धानेरा में भी गए, जहां बाढ़ के कारण भारी तबाही हुई है।

यहां रुपानी किसानों और व्यापारियों से भी मिले। इस क्षेत्र में किसान लगभग 10 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि में 4,000 टन सड़ा हुआ अनाज को डंप करने को मजबूर हो गया है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी (एपीएमसी) ने यहां हर चीज को फिर से शुरू करने के लिए राज्य सरकार से 80 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है। रुपानी ने ट्वीट कर कहा, विनाशकारी बाढ़ के कारण हुए नुकसान के उचित और समय पर मूल्यांकन होगा, इसका आश्वासन दिलाता हूं।

15 अगस्त के बाद हो सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार, कई नए चेहरे होंगे शामिल

नई दिल्ली

15 अगस्त के बाद मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। इसके साथ ही कई नए लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और मनोहर पार्रिकर के इस्तीफे के साथ ही मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई।

मिली जानकारी के अनुसार 15 अगस्त को पीएम मोदी लाल किले से भाषण के बाद 17 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में जहां कुछ नए लोगों को तवज्जो मिलने की संभावना है, वहीं उन राज्यों का भी ख्याल रखा जाएगा, जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही हाल ही में एनडीए में शामिल हुए जदयू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की संभावना है।

वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। वेंकैया नायडू मोदी कैबिनेट में कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। नायडू के पास तीन मंत्रालय थे। सूचना प्रसारण मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय। तीनों मंत्रालयों को अतिरिक्त प्रभार देने की संभावना कम ही लग रही है।

बता दें कि अरुण जेटली पहले से वित्त मंत्रालय के साथ रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। इसी साल मनोहर पर्रिकर के गोवा के मुख्यमंत्री बनने से रक्षा मंत्री का पद खाली हुआ था, वहीं पर्यावरण मंत्री अनिल दवे का निधन होने से हर्षवर्धन को पर्यावरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। हर्षवर्धन पहले से विज्ञान मंत्रालय संभाल रहे हैं।

माना जा रहा है कि मोदी सरकार का नया विस्तार मानसून सत्र के बाद 17 अगस्त को हो सकता है। इससे पहले साल 2014 में पहला केंद्रीय कैबिनेट विस्तार हुआ था। जिसमें 21 चेहरों को शामिल किया गया था। पिछले साल जुलाई में भी कैबिनेट में फेरबदल कर स्मृति ईरानी की जगह प्रकाश जावड़ेकर को मानव संसाधन मंत्रालय दिया गया था और स्मृति ईरानी को कपड़ा मंत्रालय भेज गया।

अब एक बार फिर पीएम मोदी को जिम्मेदारी देने के लिए नए चेहरे तलाशने होंगे। गुजरात और हिमाचल पदेश में अगले चार पांच महीने में चुनाव है और दो सालों के अंदर मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक समेत कई अहम राज्यों मे चुनाव होना है।

लोकसभा में गूंजा मॉब लिंचिंग का मुद्दा

नई दिल्ली

संसद का अब तक का मानसून सत्र हंगामेदार रहा है। लोकसभा में सोमवार को कांग्रेस द्वारा मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, आज पूरे देश में भय और आतंक का माहौल है, भीड़ द्वारा हत्याओं का सिलसिला थम नहीं रहा। क्या इस देश में सरकार और कानून है? 70 साल में देश में ऐसी घटनाये नहीं हुई हैं। उन्होंने आगे कहा, ऐसी घटनाओं में बीजेपी से जुड़े संगठनों का हाथ है। इन कार्यों के लिए विहिप, बजरंग दल और गौरक्षकों जैसे ग्रुप को सरकार प्रोत्साहन दे रही है। कांग्रेस नेता ने लोकसभा में भीड़ द्वारा हत्याओं वाली घटना का केंद्र झारखंड और मध्यप्रदेश को बताया। उन्होंने कहा, झारखंड व मध्यप्रदेश मॉब लिंचिंग का केंद्र बन गया है। इसके जवाब में भाजपा सांसद हुकुम देव नारायण यादव ने कहा, क्या जम्मू कश्मीर में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए डीएसपी अयूब पंडित की जिक्र आवश्यक नहीं? जब प्रधानमंत्री स्वयं ऐसी घटनाओं की बार-बार निंदा कर रहे हैं तब राज्यों को नियमों का पालन करना चाहिए।

ड्रग रैकेट मामले में तेलुगु अभिनेता तानिश अलादी से पूछताछ

हैदराबाद

तेलुगु फिल्म अभिनेता तानिश अलादी तेलंगाना उत्पाद विभाग के विशेष जांच दल (एसआइटी) के सामने हाजिर हुए। इस महीने के शुरू में उजागर हुए ऑनलाइन ड्रग रैकेट मामले की जांच में सोमवार को अभिनेता से पूछताछ हुई। तानिश अभी तक करीब 19 फिल्मों में काम कर चुके हैं। इस मामले में एसआइटी तेलुगु फिल्मोद्योग की 12 हस्तियों को अभी तक समन कर चुका है। दो जुलाई को उजागर हुए ड्रग रैकेट की जांच के दौरान तेलुगु फिल्मोद्योग से जुड़े दो नाम सामने आए थे। एसआइटी ने उनसे पूछताछ कर आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता से उनके संपर्क का पता लगाने का प्रयास किया। 19 जुलाई से कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। इनमें फिल्म निर्माता पुरी जगन्नाध, फिल्मकार श्याम के. नायडू, अभिनेता पी. सुब्बा राजू, तरुण कुमार, पी. नवदीप और रवि तेजा शामिल हैं। इस मामले में अभिनेत्री चारमी कौर और मुमैत खान, कला निर्देशक धरमा राव उर्फ चिन्ना और श्रीनिवास राव से भी पूछताछ हो चुकी है। श्रीनिवास तेजा के कार चालक थे। मामले में अभी तक 20 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें एक अमेरिकी नागरिक, एक डच नागरिक और सात बीटेक डिग्री धारक शामिल हैं। ये बीटेक डिग्रीधारक हैदराबाद में विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत हैं। जांचकर्ताओं को इस गिरोह से 1000 ग्राहकों के जुड़े होने का संदेह है। ऐसे ग्राहकों में शहर के स्कूल एवं कॉलेज के छात्र शामिल हो सकते हैं।

नीतीश कुमार ने की पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ

नई दिल्ली

बिहार में महागठबंधन से अलग होने के बाद बीजेपी के साथ सरकार बनाने के फैसले पर अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं के निशाने पर सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को सभी सवालों के जवाब दिए। जहां विपक्ष के कई नेता पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के साथ गठबंधन करने पर उनकी कड़ी आलोचना कर रहे है, वहीं नीतीश ने पीएम मोदी की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस समय पूरे देश में ऐसा कोई नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य के चुनावों में भी देशभर में मोदी का जादू चलेगा। गौरतलब है कि बिहार के सीएम के रूप में छठवीं बार शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार को पीएम मोदी ने तुरंत बधाई दे दी थी। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर कहा कि यह पहले से तय नहीं था और उनको मजबूरीवश उसके साथ जाना पड़ा क्योंकि उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर लालू यादव और आरजेडी को जिम्मेदार ठहराया। नीतीश ने विपक्ष को आगाह करते हुए कहा कि पीएम मोदी का मुकाबला करने की किसी में भी क्षमता नहीं है और 2019 में भी दिल्ली की गद्दी पर मोदी के अलावा कोई और नहीं बैठ सकता। नीतीश ने खुद के फैसले का बचाव करते कहा कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन सहयोगी के तौर पर है फॉलोअर के तौर पर नहीं। यानि नीतीश कुमार ने यहां ये स्पष्ट कर दिया कि वे हर मामले में बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे बल्कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर उनके पूरी तरह साथ होंगे।

नीतीश कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पाकिस्तान की सीमा में घुसकर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की सराहना करते हुए कहा कि हमने इसकी प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले का भी हमने कई दलों की तरह समर्थन किया।

उन्होंने कहा कि हमने एनडीए से अलग होने पर भी कई मामलों में केंद्र का समर्थन किया है।

बीजेपी के साथ गठजोड़ कर सरकार बनाने के बाद विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आए नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव पर लग रहे आरोपों के बीच मैंने उनसे कहा कि आप मुझे नहीं तो जनता के सामने ही पूरे मामले पर सफाई दें।

तेलंगाना जेल में दलित कैदियों का शोषण कर रही पुलिस - मीरा कुमार

हैदराबाद

पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने सोमवार को तेलंगाना जेल में कथित पुलिस हिंसा के शिकार दलित पीड़ित कैदियों का मामला उठाया। राज्य कांग्रेस प्रमुख उत्तम कुमार रेड्डी व अन्य पार्टी नेताओं के साथ वे करीमनगर डिस्ट्रीक्ट जेल गयीं और उन युवा कैदियों से मिलीं जिन्होंने 2 जुलाई को रजन्ना-सिरसिल्ला जिले में रेत भरे दो ट्रकों को आग लगा दी थी, जिसके लिए कथित तौर पर पुलिस ने उन्हें प्रताड़ित किया।

इसके बाद मीरा कुमार ने मीडिया को बताया कि उन्हें केवल चार पीड़ितों से मिलने की अनुमति दी गयी जबकि तीन अन्य उसी जेल में थे। उन्होंने बताया एक घायल अपराधी अभी भी अस्पताल में है। दलितों पर अत्याचार की निंदा करते हुए उन्होंने बताया कि पुलिस ने युवकों को मारा-पीटा और बिजली के झटके भी लगाए। उन्होंने बताया, पुलिस की क्रूरता को बताते हुए वे रो पड़े थे। उन्हें अंदरुनी जख्म भी हैं।

कांग्रेस नेता ने मांग की कि पीड़ितों के खिलाफ दर्ज किए गए झूठे मामले वापस लिये जाना चाहिए और जो उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं उन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत हिरासत में लिया जाना चाहिए। मामले में जांच न शुरू किए जाने पर उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की निंदा की। तेलंगाना राष्ट्र समिति पर निशाना साधते हुए उन्होंने पूछा, क्या यह वही तेलंगाना राज्य है, जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी? उन्होंने रेत माफिया के क्रियाकलापों को खत्म करने की मांग की। पूर्व स्पीकर ने कहा कि उनकी पार्टी इस मामले को संसद में उठाएगी। इस बीच सिरसिल्ला में पुलिस हिंसा के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन के लिए प्रस्तावित सार्वजनिक बैठक को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती से माहौल तनावपूर्ण है।

कांग्रेस लेगी जम्मू कश्मीर में बिहार का बदला !

नई दिल्ली

बिहार में हुए सियासी उलटफेर के बाद अब अगला नंबर जम्मू कश्मीर का है अंतर सिर्फ इतना होगा कि बिहार में भाजपा सत्ता में आई है और जम्मू कश्मीर में सत्ता से बाहर हो सकती है। पिछले तीन दिन में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा दिए गए बयान राज्य के सियासी भविष्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। जिस तरीके से महबूबा ने तिंरगे को लेकर बयान दिया है वे बयान महबूबा और मोदी के सियासी ब्रेकअप का आधार बन सकता है। महबूबा भाजपा को उकसाने के लिए इस तरह के बयान दे रही हैं और भाजपा महबूबा के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दे रही है।

महबूबा की मजबूरी

2014 में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के साथ सरकार बनाने के साथ ही महबूबा का कोर वोटर उससे नाराज हो गया और ये नाराजगी अबतक जारी है। इसका कारण पीडीपी और भाजपा का वैचारिक असमानता है। महबूबा को लगता है कि भाजपा के साथ ये सियासी गठजोड़ जितना लंबा चलेगा उतना ही पीडीपी को इसका नुकसान होगा। यही कारण है कि एनआईए और अन्य जांच एजेंसियों द्वारा अलगाववदियों पर मारे गए छापों के बाद महबूबा ने अलगाववादियों के पक्ष में स्टैंड लिया और चेतावनी भरे लहजे में यहां तक बोल गईं कि कश्मीर में तिरंगे का कोई संरक्षक नहीं बचेगा। ऐसे बयानों के जरिए महबूबा भाजपा को गठजोड़ तोडऩे के लिए उकसाने के साथ-साथ अपने कोर वोटर को संदेश भी दे रही हैं।

भाजपा क्यों मजबूर

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद पीडीपी के साथ गठजोड़ करने के वक्त से ही कश्मीर का मुद्दा भाजपा के लिए नासूर बना हुआ है। भाजपा ने कश्मीरियों के दिल जीतने के तमाम प्रयास किए लेकिन ये प्रयास विफल साबित हुए हैं और कश्मीर में शांति स्थापित नहीं हो पा रही। लिहाजा भाजपा भी पीडीपी से पिंड छुड़वाना चाहती है। 2005 के मामलों में अलगावावदियों की गिरफ्तारी इसी दिशा में भाजपा का कदम माना जा रहा है।

भाजपा को पता है कि उसकी सहयोगी पीडीपी को ये कार्रवाई रास नहीं आएगी लिहाजा भाजपा ने इस मुद्दे पर कोई समझोता न करने के लहजे में अक्रामक रुख अपना लिया है। यदि पीडीपी और भाजपा में ये गतिरोध कायम रहता है तो आने वाले दिनों में कश्मीर राजनीतिक अस्थिरता की तरफ बढ़ सकता है।

विधानसभा की स्थिति

87 सीटों की जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 28 सीटों के साथ पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी है। जबकि 25 सीटों के साथ भाजपा दूसरे 15 सीटों के साथ नेश्नल कॉन्फ्रेंस तीसरे और कांग्रेस 12 सीटों के साथ चौथे नंबर पर है। जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस के पास 2 जम्मू-कश्मीर पिपुल डेमोक्रेटिक फ्रंट के पास 1, सीपीआई के पास 1 सीटें हैं जबकि 3 सीटें आजाद विधायकों के पास है। महबूबा यदि भाजपा का साथ छोड़ती है तो भी कांग्रेस की 12 सीटों सीपीआई की 1 सीट व 3 अन्य विधायकों को मिलाकर 44 सीटों के साथ बहुमत हासिल कर सकती है और जम्मू कश्मीर में भी नीतीश कुमार की तहर बिल्कुल उसी तरह मुख्यमंत्री बनी रह सकती हैं जिस तरह जदयू ने लालू का साथ छोड़कर भाजपा के साथ सरकार बनाई है।

चीन का दुस्साहस, 6 दिन पहले भारतीय सीमा में घुसे थे सैनिक

नई दिल्ली

भारत- चीन के बीच सीमा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच चीनी सेना ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि चीनी सैनिक उत्तराखंड के बाराहोटी में एक किमी तक अंदर घुस आए थे। ये घटना 25 जुलाई सुबह 9 बजे की बताई जा रही है।

तो वहीं इस मामले पर प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि जिला प्रशासन और सुरक्षाबलों की तरफ से कोई सूचना नहीं। आपको बता दें कि चीन द्वारा की गई इस घुसपैठ के ठीक एक दिन बाद ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने चीनी समकक्ष एवं स्टेट काउंसिलर यांग जेची से डोकलाम मुद्दे पर चर्चा की थी। हालांकि अभी डोकलाम मुद्दे का कोई भी हल नहीं निकल पाया है और दोनों ही देशों के बीच सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में इस नए मामले के सामने आने से दोनों देशों के बीच विवाद और बढ़ सकता है।

मीडिया में चल रही खबरों मुताबिक चीनी सेना ने 25 जुलाई को उत्तराखंड के चमोली जिले से सटी सीमा पर घुसपैठ की है। खबर है कि चमोली जिले के बाराहोटी में चीनी सैनिक लगभग 1 घंटे तक रहे।

2016 के जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में भी चीनी सेना ने उत्तराखंड के बाराहोटी इलाके में घुसपैठ से पहले सिंथेटिक ऐपर्चर रेडार (एसएआर) से लैस उच्च श्रेणी के विमान का इस्तेमाल कर एक टोही मिशन चलाया था।

एसएआर विमान व्यापक क्षेत्र की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर उपलब्ध कराता है।